jkT;iky Jh 'k[kj nRr dk mncks/ku x.kr= fnol 26 tuojh 2010 ifyl
ijM ednku] jk;ij

e|j I;kj Hkkb;ks vkj cguks]

भारतीय गणतंत्र की साठवीं सालगिरह की मंगलबेला में सबसे पहले मैं उन अमर शहीदों और मनीषियों को सादर नमन करता हूं, जिनके त्याग और बलिदान से हमारा गौरवशाली गण–तंत्र इस ऊंचाई तक पहुंचा है। इस अवसर पर आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।

2- आज का दिन हर्ष और उल्लास के साथ महान राष्ट्रीय पर्व मनाने का और यह आत्मावलोकन करने का भी है कि देश के महान संविधान में निहित भावनाओं और संकल्पों पर हम कितने खरे उतरे हैं। इसके लिए हम किस हद तक समर्पण और त्याग के लिए तत्पर हैं। हमारी निष्ठा ही, हमारे गणतंत्र की सफलता का मूलमंत्र है।

3- मुझे खुशी है कि छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र की मजबूती को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद नगरीय निकायों और त्रि–स्तरीय पंचायतराज संस्थाओं के चुनाव भी निर्धारित समय पर कराने की प्रतिबद्धता से राज्य में व्यवस्था के प्रति विश्वास मजबूत हुआ है।

4- संविधान और लोकतंत्र को नहीं मानने वाले नक्सलवादी तत्वों द्वारा की गई हिंसा और साजिशों के खिलाफ छत्तीसगढ़ की जनता का उठ खड़ा होना शुभ संकेत है। आपके समर्थन से नक्सलवाद प्रभावित तथा वनों से घिरे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का मनोबल बढ़ा है। नक्सली हिंसा में शहीद हुए पुलिस के अधिकारियों, सुरक्षाबलों के जवानों और जनता का बलिदान खाली नहीं जाएगा, इसके लिए सरकार हर सम्भव कदम उठा रही है। निर्णायक दौर में हिंसा का काला अध्याय समाप्त करने के लिए सरकारी प्रयासों के साथ, आपका लगातार और सक्रिय समर्थन भी आवश्यक है।

5- छत्तीसगढ़ की सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियां प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए बहुआयामी और बहुस्तरीय प्रयासों की जरूरत रेखांकित करती हैं, इसलिए राज्य

में एक ओर जहां विकास की दौड़ में पीछे छूट गए तबकों को विशेष सुविधाएं देकर तेजी से आगे लाने की रणनीति अपनाई गई। वहीं दूसरी ओर राज्य की प्रखर संभावनाओं को चिन्हांकित कर उन क्षेत्रों में विकास के द्वार खोले गए। मुझे खुशी है कि राज्य की जनता ने इस रणनीति का साथ दिया और विभिन्न योजनाओं में शामिल होकर विकास कार्यों में भागीदार बनी।

6- छत्तीसगढ़ में अन्य संसाधनों की तरह मानव संसाधन विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। इस दिशा में किए गए कुछ अभिनव प्रयासों का जिक्र करना चाहूंगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिए जो निःशुल्क पायलट प्रशिक्षण योजना लागू की गई है, उससे प्रशिक्षित नौजवान अब कमर्शियल पायलट का लायसेंस पाने लगे हैं। अनुसूचित जनजाति की जिन युवतियों को एयर होस्टेस प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उनमें से दस युवतियों को रोजगार भी मिल चुका है। निःशुल्क सायकल प्रदाय योजना से आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवारों की बेटियां बड़ी संख्या में हाईस्कूल, हायरसेकेण्डरी की पढ़ाई करने लगी हैं। इसी तरह मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना, विशेष शिक्षण केन्द्र योजना, कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना, छात्रावास–आश्रम योजना, एकीकृत आदिवासी विकास योजना, वाहन चालक प्रशिक्षण, नर्सिंग पाठ्यक्रम जैसे अनेक प्रयासों का नतीजा सकारात्मक रहा है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अंचलों के लिए गठित विकास प्राधिकरणों ने भी अपनी सार्थकता सिद्ध की है।

7- पढ़ाई को सुविधाजनक और रोचक बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस वर्ष चार सौ पांच प्राथमिक विद्यालय, नौ हाईस्कूल, इकतीस हायर सेकेण्डरी और सत्रह नाइट शेल्टर स्कूल शुरू किए गए हैं। करीब पन्द्रह हजार शाला भवनों तथा अतिरिक्त कक्षों के निर्माण की मंजूरी दी गई। बड़े पैमाने पर शिक्षाकर्मियों की भर्ती से शिक्षकों का अभाव दूर होगा। परीक्षा प्रणाली में सुधार से प्रौढ़ एवं पढ़ाई छोड़ चुके लगभग सात लाख लोगों का पांचवीं एवं आठवीं परीक्षा में उत्तीर्ण होने का सपना पूरा हुआ है। दूरवर्ती शिक्षा में एड्यूसेट के उपयोग हेतु नब्बे सेटेलाइट टर्मिनल लगाए जा रहे हैं।

प्राथमिक, माध्यमिक शालाओं के पर्याप्त संख्या में संचालन के बाद अब हर पांच किलोमीटर पर हाई स्कूल खोलने का लक्ष्य रखा गया है। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सायकल, गणवेश, पाठ्यपुस्तकें, कम्प्यूटर शिक्षा जैसी सुविधाएं निःशुल्क देने के अलावा जगदलपुर और बीजापुर विकासखण्ड में 'धनलक्ष्मी योजना' भी संचालित की जा रही है। अंबिकापुर में इंजीनियरिंग कॉलेज तथा रायपुर में आईआईएम की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, जशपुर, कोरिया, दंतेवाड़ा, गरियाबंद, रायपुर में पॉलीटेक्निक शीघ्र प्रारम्भ किए जाएंगे। प्रदेश के पैंसठ महाविद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित किए गए हैं। उच्च शिक्षा में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए चवालीस में से तेइस महाविद्यालय आदिवासी अंचलों में स्थापित किए गए हैं। प्रत्येक विकासखण्ड में एक महाविद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा गया है।

8- मानव संसाधन का शिक्षित होने के साथ सेहतमंद होना भी जरूरी है। इसके लिए छत्तीसगढ़ में जनस्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं के विस्तार हेतु अनेक कदम उठाए गए हैं। चिकित्सकों, ग्रामीण चिकित्सा सहायकों, स्टाफ नर्स, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की नियुक्ति बड़े पैमाने पर की जा रही है। बेहतर अधोसंरचना के लिए स्वास्थ्य संस्थाएं, प्रशिक्षण केन्द्र, औषधि भण्डार आदि के लिए भवनों का निर्माण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना जैसे उपायों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया गया है।

9- करीब तीन वर्ष पहले राज्य में गरीब परिवारों को खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान करने की योजना शुरू की गई थी। जिसकी सफलता ने अन्य प्रदेशों और देश के नीति नियामकों को भी प्रेरित किया है। वहीं छत्तीसगढ़ में यह योजना नए विस्तार के साथ जुलाई, 2009 से प्रारम्भ कर दी गई है। जिसके तहत अंत्योदय परिवारों को एक रूपए किलो में और अन्य गरीब परिवारों को दो रूपए प्रति किलो में प्रतिमाह पैंतीस किलो चावल दिया जा रहा है। 'छत्तीसगढ़ अमृत नमक' योजना के तहत हर गरीब परिवार

को प्रति माह दो किलो आयोडाइज्ड नमक निःशुल्क दिया जा रहा है। इसके साथ ही कुपोषण मुक्ति अभियान नई ऊर्जा के साथ शुरू किया गया। राज्य शासन की प्रेरणा से स्वयंसेवी व्यक्ति एवं संस्थाओं ने तेरह हजार गंभीर कुपोषित बच्चों को गोद लिया है। मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना के तहत कुपोषित बच्चों के उपचार में आंगनवाड़ी केन्द्रों को भागीदार बनाया गया है।

10- गांव–गांव में शुद्ध पेयजल पहुंचाने का काम निनानबे प्रतिशत पूरा हो चुका है। इसी तरह साठ नगरीय निकायों में नल–जल योजनाएं क्रियान्वित की जा चुकी हैं तथा अन्य नगरीय निकायों में कार्य प्रगति पर है। आगामी तीन वर्षों में सभी नगरीय निकायों में स्वच्छ पेयजल सुलभ कराने का लक्ष्य है। पेयजल की गुणवत्ता के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण तथा परीक्षण किट दिया जा रहा है।

11- राज्य सरकार ने सिंचाई का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत के बराबर लाने की बड़ी चुनौती स्वीकार की है। नई परियोजनाओं के निर्माण के साथ, वर्षों से लंबित परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने की रणनीति अपनाई गई है। इस तरह घुमरिया, सूखानाला, कर्रानाला, मध्यम परियोजनाओं और केलोवृहद परियोजना का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। बस्तर की कोसारटेडा परियोजना पूरी की जा चुकी है। इसके अलावा निर्मित सिंचाई क्षमता और वास्तविक सिंचाई क्षमता के बीच का अंतर कम करने के लिए छत्तीसगढ़ सिंचाई योजना शुरू की गई है, जिसके तहत तीन सौ करोड़ रूपए से अधिक लागत की एक सौ सढ़सठ परियोजनाओं में पुनरूद्धार और नवीनीकरण का काम प्रगति पर है। नदियों पर एक सौ चार एनीकट बनाए जा चुके हैं और एक सौ दस एनीकट का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

12- राज्य में अच्छी अधोसंरचना विकसित करने का अभियान चलाया गया है। पक्की सड़कों, पुल–पुलियों, रेल्वे ओव्हर ब्रिज, रेल्वे अंडर ब्रिज जैसी संरचनाओं के निर्माण में तेजी लाई गई है। नियमित कार्यों के अलावा विशेष प्रयासों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सड़क परियोजना के तहत करीब बारह सौ पचास किलोमीटर लम्बी पैकेज सड़कों में से अधिकांश का काम पूरा हो गया है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र योजना में सोलह सौ

किलोमीटर सड़कें बनाई जाएंगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में करीब इकतीस सौ सड़कें और उन्नीस हजार से अधिक पुल–पुलिया बनाई जा चुकी हैं। घरेलू वायु सेवा शुरू करने की अभिनव पहल भी की गई है। जिसके तहत रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जशपुर, अम्बिकापुर और जगदलपुर को जोड़ने की योजना है। इस तरह राज्य में एक कोने से दूसरे कोने में पहुंचना काफी आसान हो जाएगा। अंतर्राज्यीय परिवहन को भी बेहतर बनाने के लिए परिवहन, वाणिज्यिक कर, खनिज, वन एवं कृषि उपज मंडी की एकीकृत जांच चौकियां स्थापित की जा रही हैं।

13- इसी तरह ग्रामीण विकास में भी समन्वित रणनीति अपनाई गई है। तेरह जिलों में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के माध्यम से दो सौ साठ करोड़ रूपए की लागत से अधोसंरचना विकास के कार्य कराए जा रहे हैं। इस साल पचपन करोड़ रूपयों की लागत से ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना निर्माण के लगभग अठारह सौ कार्य कराए जा रहे हैं। ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्व वाले स्थलों में भी बीस करोड़ रूपए की लागत से अधोसंरचना विकास के कार्य कराए जा रहे हैं।

14- बेहतर आमदनी के लिए रोजगार के बेहतर साधनों का होना जरूरी है। यही वजह है कि राज्य शासन ने हर वर्ग की जरूरतों का ध्यान रखकर बहुस्तरीय प्रयास किए हैं। सबसे पहले किसानों की बात करता हूं। उन्हें प्रमाणित बीज, खाद, उपकरण, सुलभ कराके लाभदायक फसलों का रकबा बढ़ाया गया। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, देश में सबसे सस्ता कृषि ऋण, पांच हार्स पावर के पम्पों को निःशुल्क बिजली, नलकूपों और सिंचाई पम्पों के लिए आकर्षक अनुदान देने की योजनाओं से किसानों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हुई और उनका मनोबल भी बढ़ा है।

15- वनवासी भाई, बहनों की वनोपज के कारोबार में निर्भरता को देखते हुए तेन्दूपत्ता और साल बीज संग्रहण का पारिश्रमिक दोगुना तक किया गया। उन्हें विगत एक वर्ष में पारिश्रमिक और बोनस के रूप में दो सौ पचास करोड़ रूपए से अधिक की राशि दी गई है। वनोपज प्रसंस्करण केन्द्रों की स्थापना की जा रही है।

16- रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में सुनिश्चित रोजगार प्रदान करने के लिए प्रभावी रणनीति अपनाई गई है। राज्य के दो जिलों को बेहतर क्रियान्वयन के लिए पुरस्कृत किया जाना कार्य की सही दिशा का प्रतीक है। चौंतीस लाख इकहत्तर हजार परिवारों को पंजीयन उपरांत रोजगार कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं। पचपन लाख से अधिक श्रमिकों के खाते बैंक और पोस्ट ऑफिस में खोले गए हैं। इस वर्ष मांग के आधार पर करीब सोलह लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। नवा अंजोर परियोजना में लगभग इक्कीस हजार समहित समूहों के लिए विकासखंडों में विपणन केन्द्रों की स्थापना की जा रही है। इसी तरह स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के कारण इस वर्ष बत्तीस हजार से अधिक हितग्राहियों को लगभग एक सौ पन्द्रह करोड़ रूपए का ऋण एवं अनुदान दिया गया है। हर जिले में तीन–तीन ग्रामीण हाट का निर्माण किया जा रहा है। ग्यारह जिलों में राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान प्रारम्भ किए गए हैं। हाथकरघा, हस्तशिल्प जैसे रोजगार के परम्परागत साधनों को नया जीवन देकर करीब दो लाख परिवारों को खुशहाली के रास्ते पर लाया गया है।

17- महिला स्व–सहायता समूहों के माध्यम से करीब नौ लाख महिलाओं को रोजगार के नए–नए अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। एक नई पहल के तहत आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए रेडी–टू–ईट पोषण आहार बनाने और प्रदाय का कार्य भी इन समूहों को सौंपा जा रहा है। नए उद्योगों में स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के अलावा नई 'औद्योगिक नीति 2009–14' में कमजोर तबकों, महिलाओं, विकलांगों, सेवानिवृत्त सैनिकों एवं नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्तियों को सामान्य वर्ग की अपेक्षा दस प्रतिशत अधिक अनुदान, छूट एवं रियायत दी गई है।

18- अपने घर का सपना हर व्यक्ति की आंखों में होता है। गरीबों के इस सपने को पूरा करने के लिए दीनदयाल आवास योजना, डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी आवास योजना, अटल आवास योजना के तहत गरीबों को काफी रियायती दरों पर तथा विशेष पिछड़ी

जनजातियों के करीब आठ हजार परिवारों को निःशुल्क पक्के आवास बनाकर दिए जा रहे हैं। भूमिहीन ग्रामीण परिवारों को भूमि का पट्टा दिया जा रहा है।

19- राज्य की प्राकृतिक सम्पदा, खनिजों की अच्छी गुणवत्ता तथा बहुतायत में उपलब्धता पर गौरव की अनुभूति स्वाभाविक है लेकिन खनिज संसाधनों का विकास और खनिज राजस्व में बढ़ोत्तरी एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। इस दिशा में राज्य शासन के सतत् प्रयासों से एड–वेलोरम रायल्टी मिलना एक बड़ी उपलब्धि है। राज्य गठन के समय यहां का खनिज राजस्व लगभग चार सौ करोड़ रूपए था, जो अब सोलह सौ करोड़ रूपए से अधिक हो गया है।

20- राज्य में बिजली, सीमेन्ट, लौह एवं इस्पात, एल्यूमीनियम उत्पादन की संभावनाओं को चिन्हांकित करके विभिन्न संस्थाओं के साथ जो करार किए गए उसमें बीस हजार करोड़ रूपए का पूंजी निवेश हो चुका है। पिछड़े जिलों जैसे सरगुजा जिले के नयनपुर– गिरवरगंज, महासमुन्द जिले के बिरकोनी में लघु उद्योगों की स्थापना हेतु लघु उद्योग क्षेत्र स्थापित हो चुके हैं एवं राजनांदगांव जिले के महरूमखुर्द, जांजगीर–चांपा के कापन एवं दंतेवाड़ा जिले के टेकनार क्षेत्र में लघु औद्योगिक क्षेत्र बनाए जा रहे हैं।

21- बिजलीघरों की कार्य क्षमता में वृद्धि और नए बिजलीघरों की स्थापना से राज्य में विद्युत उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। पारेषण तथा वितरण प्रणाली में भी विस्तार किया गया है। इन प्रयासों से ओव्हर लोडिंग और लो–वोल्टेज की समस्या को हल किया जा रहा है। वहीं विद्युत क्षेत्र में भी जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। किसानों को करीब एक लाख चालीस हजार नए सिंचाई पम्प कनेक्शन देकर एक नया इतिहास रचा गया है। सभी वर्गों के किसानों को पांच हार्स पॉवर क्षमता तक के पम्पों पर सालाना छह हजार यूनिट तक निःशुल्क विद्युत प्रदाय के लिए 'कृषक जीवन–ज्योति योजना' प्रारम्भ की गई है। इस पर हर साल लगभग एक सौ बत्तीस करोड़ रूपए का खर्च राज्य शासन वहन करेगा।

22- औद्योगिक विकास के साथ पर्यावरण का संरक्षण भी आवश्यक है। राज्य सरकार ने इस संबंध में कड़े रूख का परिचय देते हुए प्रदूषक उद्योगों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की है। उद्योगों को पर्यावरण संरक्षण के उपाय अपनाने हेतु प्रेरित किया गया है। वहीं जलाशयों के संरक्षण हेतु भी राज्यव्यापी अभियान व्यापक जनभागीदारी के साथ संचालित किया गया है। ऐसे उपाय निरंतर जारी रखे जाएंगे और इसमें व्यापक समाज अपनी भूमिका अदा करे।

23- राज्य में इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी को अधोसंरचना का प्रमुख हिस्सा माना गया है। सूचना प्रौद्योगिकी के वरदान से राज्य के कोने–कोने को लाभान्वित करने के लिए स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क 'स्वान' की स्थापना सभी विकासखंडों में की गई है। छत्तीसगढ़ एक मात्र राज्य है, जिसने इस कार्य के लिए 'सैटेलाइट हब स्टेशन' बनाया है। शहरी चॉइस परियोजना की तरह नागरिक सेवाओं को ग्रामीण स्तर तक पहुंचाने के लिए राज्य में छह ग्राम समूहों के बीच एक के मान से चौदह सौ से अधिक 'सामान्य सेवा केन्द्र' प्रारम्भ किए जा चुके हैं।

24- छत्तीसगढ़ की वैभवशाली विरासत और समृद्ध संस्कृति में भाईचारे और एकता की अद्‌भुत क्षमता है। इसके संरक्षण और संवर्धन के सतत् प्रयास, यह विश्वास मजबूत करते हैं कि यह राज्य शांति का टापू बना रहेगा लेकिन मैं इसे जनहितकारी विकास का प्रकाशस्तम्भ कहना ज्यादा पसंद करता हूं। मेरा मानना है कि जब कोई सरकार अलग–अलग परिस्थितियों में रहने वाले हर वर्ग के व्यक्ति के लिए हितकारी योजनाएं बनाने और अपनाने को प्राथमिकता देती है, तो उसके मूल में हर व्यक्ति को गरिमा के साथ जीने के योग्य वातावरण उपलब्ध कराने की भावना होती है। इससे देश और संविधान निर्माताओं के सपनों को सच करने का जज्बा दिखता है।

25- आमजनों की खुशहाली में बढ़ोत्तरी गणतंत्र की मजबूती में आप सबकी भागीदारी का प्रतीक है। मेरी शुभकामनाएं है कि आप सबके सहयोग से राज्य हर क्षेत्र में नई–नई उपलब्धियां हासिल करे। नक्सली हिंसा और आतंक का सफाया हो ताकि प्रभावित अंचलों में विकास का सूरज पूरी प्रखरता से चमके। विकास कार्यों को स्थायित्व मिले। आप सबकी लगन, मेहनत और समर्पण को देखते हुए मुझे लगता है

कि छत्तीसगढ़ को देश का अग्रणी राज्य बनाने का आपका सपना जल्दी ही पूरा होगा।